12 भारत में नगरीकरण की समस्याएँ (Problems of Urbanisation in India)

भारत में नगरीय समस्याएँ (Urban Problems in India)

भारत में औद्योगीकरण के विकास ने अन्य तथ्यों के साथ मिलकर नगरीकरण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परिणामत: नगरीय विकास के साथ ही विभिन्न नगरीय समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं। इन समस्याओं को निम्न रूपों में देखा जा सकता है:–

सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याएँ (Socio-Cultural Problems)

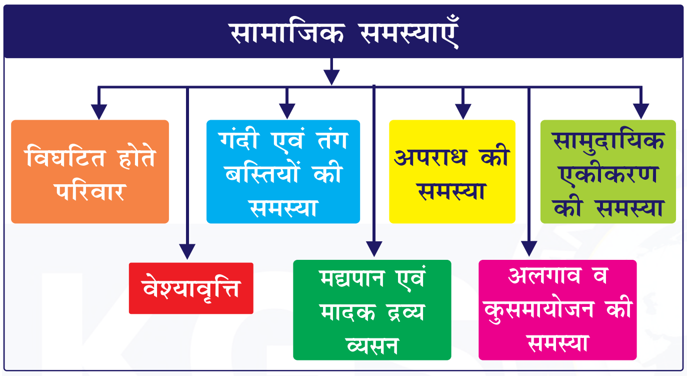

विघटित होते परिवार (Disintegrating Family)

नगरीकरण की प्रक्रिया में पारिवारिक सम्बन्धों में बिखराव के साथ संयुक्त परिवारों (Joint Family) का विघटन हो रहा है। इसी के फलस्वरूप नगरीय परिवार के सम्मुख अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं जो कि निम्नलिखित हैं:–

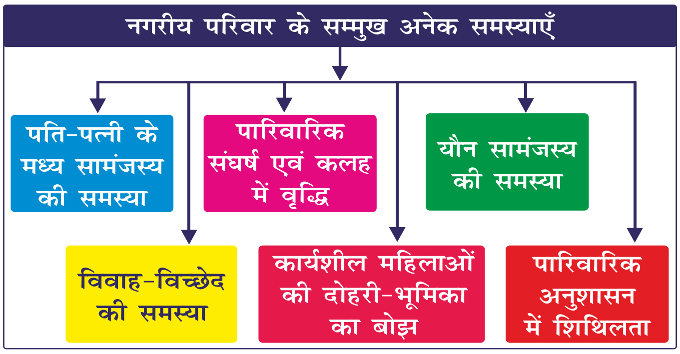

वेश्यावृत्ति (Prostitution)

आधुनिक औद्योगिक नगरों की अपनी संरचनात्मक विशेषताएँ (Structural Features) हैं, जिन्होंने नगरों में वेश्यावृत्ति को फलने-फूलने का अवसर दिया है। इसमें गुप्त एवं सुरक्षित स्थान, अनजानापन आदि प्रमुख हैं। महानगरों में वेश्यावृत्ति अब मनोरंजन केन्द्रों तक सीमित नहीं है अब यह उच्च वर्गीय अपार्टमेंट में जहाँ लोग ऊँची कीमत दे सकें से लेकर गन्दी बस्तियों तक फैल चुका है।

आज केवल गरीब व शोषित महिला ही इससे नहीं जुड़ी है अपितु आज हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल भी काफी संख्या में मौजूद है जो अपने भौतिकवादी महत्वाकांक्षा (Materialistic Ambition) की पूर्ति हेतु वेश्यावृत्ति में संलग्न है।

गंदी एवं तंग बस्तियों की समस्या (Problem of Dirty and Crowded Slums)

नगरीकरण की तेज गति के फलस्वरूप नगरों में गंदी बस्तियों की समस्या एक बड़ी सामाजिक समस्या के रूप में उभरी है। यह नगरों में आवास की समस्या से परिणामिक (Consequential) रूप से जुड़ी है। नगरीय आबादी का लगभग पाँचवां भाग गंदी और तंग बस्तियों में रहता है।

गंदी बस्तियाँ सांस्कृतिक व सामाजिक विघटन (Social Dissolution) के केन्द्र होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में शराबखोरी, मादक द्रव्य व्यसन, वेश्यावृति जैसी सामाजिक समस्याओं का सकेन्द्रण देखा जा सकता है। गन्दी बस्तियों में अपराधियों के छुपने की जगह भी मुहैया कराते हैं।

मद्यपान एवं मादक द्रव्य व्यसन (Alcoholism and Drug Addiction)

वैसे तो नगर एवं ग्रामीण दोनों समाजों में मद्यपान एक गंभीर समस्या के रूप में उभर रहा है पर 20वीं सदी के अंत में महानगरों में कुछ ऐसे कारक रहे हैं जिन्होंने इसे और भी गंभीर बना दिया है। अब शराब पीना महानगरीय संस्कृति का अंग बनता जा रहा है। महानगरीय युवाओं में शराब सेवन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। नए विकसित संचार माध्यमों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नगरीय समाज का एक बहुत बड़ा भाग मजदूरों एवं उद्योगों के श्रमिकों से मिलकर बना है। यह वर्ग अपनी शारीरिक थकान मिटाने के लिए शराब का सेवन करना आवश्यक समझता है।

मद्यपान के अतिरिक्त नगरों में मादक-द्रव्य व्यसन की समस्या में भी वृद्धि हुई है। आज नगरों में रेव पार्टियों के प्रचलन में वृद्धि हुई है। पब व डांस क्लब मादक द्रव्य व्यसन के अड्डे बन गए हैं। मादक-द्रव्य व्यसन के कारण व्यक्तिगत विघटन के साथ-साथ सामुदायिक विघटन (Community Dissolution) की समस्याओं में भी वृद्धि हो रही है।

मद्यपान एवं मादक द्रव्य-व्यसन युवाओं को अपराध व हिंसा की ओर उन्मुख कर रहे हैं।

अपराध की समस्या (Problem of Crime)

पिछले कुछ दशकों में नगरीकरण की तेज गति ने विकसित तथा विकासशील समाजों में अपराध की समस्या को जन्म दिया

है। संसार के सभी महानगर तथा बड़े नगर अपराध तथा बाल अपराध हेतु अनुकूल अवसर प्रदान करते हैं। भारत में भी ग्रामीण तथा आदिवासी इलाकों की तुलना में नगरों में अपराध की दर उच्च हैं। नगरीकरण की बढ़ती दर के साथ अपराध की दर भी बढ़ती है क्योंकि सफलता के लिए संस्थागत अवसर, आकांक्षा रखने वालों की तुलना में कम होते हैं। इसके साथ ही नगर की अपरिचित परिस्थिति भी अवैध-क्रियाओं के लिए सामाजिक अनुकूलता (Social Compatibility) प्रदान करती है।

क्योंकि, इन दशाओं में कानून तथा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार परंपरागत सामाजिक नियंत्रण की संस्थाएँ कमजोर पड़ जाती हैं। पाश्चात्य समाजों की तुलना में भारत के नगरों में अपराध की दर कम है, फिर भी बड़े नगरों की आबादी में अभूतपूर्व वृद्धि तथा व्यापक आर्थिक असुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के कारण फौजदारी अपराधों के साथ ही आर्थिक अपराध चाहे वह 'ब्लू-कॉलर' हो या 'व्हाइट-कॉलर' अत्यन्त तेजी से बढ़ रहे हैं।

अलगाव व कुसमायोजन की समस्या (Isolation and Maladjustment Problem)

नगरीकरण की प्रक्रिया में नगरीय सामाजिक जीवन में सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विषमताओं, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष तथा सामाजिक जटिलता के अनन्य पक्षों की अभिव्यक्ति होती है। ऐसी स्थिति में भिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश (Socio Cultural Environment) के लोग जब नगरीकरण की प्रक्रिया में एक दूसरे के निकट आते हैं तो पारस्परिक समायोजन (Mutual Adjustment) उनके नगरीय सामाजिक जीवन की प्राथमिक शर्त होती है। जिन व्यक्तियों में निराशा, हीनता तथा सामाजिक असुरक्षा की भावना जैसी मानसिक विकृतियाँ पैदा होती हैं उनमें नगरीय समाज से अलगाव उत्पन्न होता है और वे मूल्यहीनता (Valuelessness) की स्थिति में आ जाते हैं। उनका यह मानसिक अन्तर्द्वन्द प्रथमतः सामाजिक कुसमायोजन उत्पन्न करता है जिसकी परिणति आपराधिक गतिविधियों के रूप में होती है। नगरों में होने वाली हत्याएं, बलात्कार, डकैती आदि परम्परागत अपराधों के पीछे इस अलगाव व कुसमायोजन को देखा जा सकता है।

सामुदायिक एकीकरण की समस्या (Problem of Community Integration)

अल्पसंख्यक समुदायों का गांवों से नगरों की ओर प्रवास नगरीय सामाजिक पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इनके शहरी सामाजिक संरचना में एकीकृत होने की समस्या सदैव विद्यमान रही है।

नगरों में प्रवासियों द्वारा कई बार स्थानीय सदस्यों की जीवनशैली को नहीं अपनाया जाता है बल्कि इसके विपरीत अपने पृथक निवास स्थानों, अपने निजी समुदाय संस्थाओं और संघों की स्थापना कर लेते हैं। इसी प्रकार के एकीकरण की प्रक्रिया हम बंगालियों, पंजाबियों, केरलवासियों, तमिलों, महाराष्ट्रियों और कश्मीरियों में भी देख सकते हैं जो अपने मूल नगरों से दूसरे राज्यों के नगरों में जाकर बस जाते हैं। वे केवल अपने संघ ही नहीं बनाते बल्कि विशेष अवसरों पर एक दूसरे से मिलते भी हैं जहाँ वे अपनी सामाजिक प्रथाओं का पालन करते हैं। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि पड़ोसियों के साथ सम्बन्धों में आक्रामक व्यवहार दिखाई देता है। यहाँ महाराष्ट्रियों का अपने उन पड़ोसियों के साथ नकारात्मक व्यवहार दिखाई दिया जो अन्य क्षेत्रों से आए थे। परन्तु, महाराष्ट्रीय लोग शिव सेना के आदर्शों से अधिक प्रभावित हैं इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इसी प्रकार की विचारधारा देश के अन्य भागों में विभिन्न नृजातीय समूहों (Racial Groups) के बीच सम्बन्धों को निर्धारित करती है।

अति-नगरीकरणजनित समस्या (Problem Caused by Over-urbanization)

नगरीय आबादी का इतना ज्यादा बढ़ जाना कि शहर अपने निवासियों को एक अच्छी जीवनशैली देने में असफल हो जाए तो यह स्थिति अतिनगरीकरण कहलाती है। इससे जन-सुविधाओं एवं मकानों पर अत्यधिक आबादी का दबाव बढ़ जाता है। भारतीय संदर्भ में अतिनगरीकरण के कई प्रभाव रहे हैं, जैसे-,

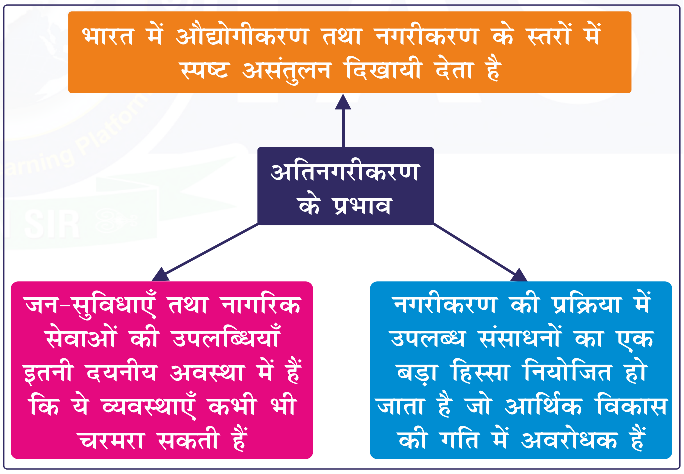

भारत में तीव्र नगरीकरण शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संसाधनों के आवंटन में असंतुलन उत्पन्न कर रहा है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक विकास की गति पर प्रतिकूल असर पड़ा है। भारत में नगरीय समस्याएँ केवल अतिनगरीकरण का परिणाम ही नहीं हैं बल्कि इसको मुख्यतः नगरीकरण के स्वरूप को संचालित करने वाली प्रभावपूर्ण नगरीय नीति के अभाव के परिणाम के रूप में भी देखा जा सकता है।

आवास की समस्या (Problem of Housing)

नगरीय जनसंख्या में हो रही तीव्र वृद्धि ने अनेकों समस्याओं को जन्म दिया है जिसमें सबसे बड़ी समस्या आवास की है।

नगरवासियों का एक विशाल भाग अति दयनीय आवासों और तंग-बस्तियों में रहता है। अनुमानतः बड़े-बड़े नगरों के लगभग 70 प्रतिशत लोग निम्न स्तर के मकानों में रहते हैं। इसी प्रकार सैकड़ों ऐसे व्यक्ति हैं जो शहरों में 'फुटपाथों' पर बिना किसी आश्रय के जीवन व्यतीत करते हैं।

सुरक्षित और पर्याप्त जल-आपूर्ति की समस्या (Problem of Safe and Adequate Water Supply)

नगरों में घरेलू उपयोग के लिए जल की उपलब्धता एक आधारभूत आवश्यकता (Basic Need) है। परंतु, भारत सहित तृतीय विश्व के देशों के नगरों में कुछ ही नगरवासी ऐसे हैं जो इस सुविधा को लगातार एवं संतोषजनक रूप से प्राप्त कर रहे हैं।

भारत में लगभग 30 प्रतिशत नगरवासी शुद्ध पेय जल की सुविधाओं से वंचित (Debrived) हैं। नगरों तथा शहरों में पानी प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत नगरपालिकाओं के नल तथा हैण्ड पम्प हैं। किंतु ज्यादातर नगरों में, विशेषतः तेजी से बढ़ रहे नगरों में, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को घरेलू उपयोग हेतु सुरक्षित जल की प्राप्ति में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

प्रभावी और पर्याप्त परिवहन की समस्या (Problem of Effective and Adequate Transportation)

एक अच्छी व संतुलित परिवहन व्यवस्था नगरवासियों को निवास और काम के स्थल के बीच तथा प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आना-जाना सुगम बनाती है। इस तरह की परिवहन व्यवस्था उन लोगों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है जो रोजी-रोटी के लिए नगरों पर आश्रित होते हैं पर नगर में स्थायी निवास करने के बजाय गाँव से प्रतिदिन नगर में आते-जाते हैं।

भारत के नगरों में एक तरफ संकीर्ण और तंग सड़कें व गलियाँ एवं उनकी दयनीय स्थिति तथा दूसरी तरफ भीड़-भाड़ व जाम ट्रैफिक का भयावह दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जो लगभग नगर के प्रत्येक भाग में, खासतौर से व्यापारिक क्रियाओं के इलाकों तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दिखाई देता है।

पर्यावरण प्रदूषण की समस्या (Problem of Environmental Pollution)

वर्तमान समय में औद्योगीकरण एवं नगरीय विकास ने सम्पूर्ण विश्व के समक्ष पर्यावरण प्रदूषण जैसी भयानक समस्या को जन्म दिया है। भारत में कोलकाता, मुम्बई, कानपुर तथा दिल्ली जैसे शहर घनी आबादी के साथ ही प्रथम श्रेणी के प्रदूषित शहर हैं। अन्य शहरों की स्थिति भी दिन-व-दिन खराब होती जा रही है।

नगरों में बढ़ते प्रदूषण के कारकों में भीड़-भाड़ भरी सड़कें, लगातार बढ़ रहे परिवहन के साधन, सीवेज, परम्परागत घरेलू ईंधन, औद्योगिक कारखाने तथा गंदी बस्तियाँ आदि प्रमुख हैं।

प्रौद्योगिकीय प्रदूषण (Industrial Pollution) के स्रोतों के साथ ही पर्यावरण प्रदूषण के कारणों में मानवीय गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पर्यावरण की स्वच्छता के बारे में नगरवासियों तथा उद्योगपतियों की लापरवाही, स्थानीय अधिकारियों की पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रामाणिक मानदंडों (Criteria) के प्रति उपेक्षा, उपलब्ध जमीन पर स्वार्थी समूहों का आधिपत्य और जन-सुविधाओं, जैसे -शौचालय, गटर, कूड़ा-करकट इकट्ठा करने की पेटियाँ, नल तथा स्नानाघर की दयनीय हालत नगर के वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। नगरीकरण की लगातार बढ़ती दर एवं उपलब्ध जमीन पर आबादी के बढ़ते दबाव के फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण नगरवासियों के स्वास्थ्य तथा सुखमय जीवन के लिए एक चुनौती के रूप में उपस्थित हुआ है।

नगरीय समस्याओं के कारण (Causes of Urban Problems)

भारत में नगरीकरण ने जिन विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है, उनके लिए निम्न कारण उत्तरदायी हैं:-

1. ***व्यक्तिवादिता तथा तीव्र प्रतिस्पर्धा (Individualism and Intense Competition)*** – नगरीय समाज में व्यक्तिवादिता एक प्रमुख विशेषता बन गयी है। व्यक्ति अधिकाधिक आत्मकेन्द्रित (Self Centric) होता जा रहा है तथा धनसंपत्ति को ही अधिक महत्व देता है। अधिक से अधिक धन संग्रह की प्रवृत्ति में व्यक्ति को तीव्र प्रतिस्पर्धा हेतु मजबूर किया है। उपरोक्त प्रवृत्ति कई सारी नगरीय समस्याओं के लिए एक महत्वपूर्ण कारण है।
2. ***उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार (Spread of Consumerist Culture)*** – आज नगरीय समाज में उपभोक्तावादी संस्कृति अपने चरम पर है। लोग दिखावे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। नगरों में व्यक्ति की प्रस्थिति (Status) उसकी आय या जाति से निर्धारित न होकर अपितु उसके उपभोग के स्तर से निर्धारित होती है।

दिखावे की संस्कृति की यह होड़ कई सारी नगरीय सामाजिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है।

3. ***जनसंख्या विस्फोट (Population Explosion)*** – नगरीकरण की अधिकता तथा इससे उत्पन्न विभिन्न समस्याओं हेतु सबसे प्रमुख उत्तरदायी कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति का होना है। नगरों में आवास, परिवहन, प्रदूषण तथा अन्य समस्याओं के लिए जनसंख्या विस्फोट की स्थिति सर्वाधिक जिम्मेदार है।

4. ***नगरीय क्षेत्रों में नागरिक संस्कृति का अभाव (Lack of Civic Culture in Urban Areas)*** – नगरों में विभिन्न वर्गों व समुदायों के लोग एक साथ रहते हैं जिसके परिणामस्वरूप सांस्कृतिक विविधता (Cultural Diversity) की स्थिति पायी जाती है। ऐसे में किसी सामान्य नागरिक संस्कृति का अभाव हो जाता है जो नगरीय अपराध व संघर्ष की समस्या को उत्पन्न करता है।

5. ***तीव्र-ग्रामीण नगरीय प्रवास (Rapid Rural Urban Migration)*** – ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में कमी तथा नगरीय आकर्षण से उत्पन्न ग्रामीण-नगरीय प्रवास ने शहरों में जनसंख्या के दबाव को बढ़ाकर संबंधित समस्याओं को जन्म दिया है। गंदी बस्तियों का फैलाव, अपराध जैसी समस्याओं के लिए यह प्रमुख रूप से उत्तरदायी है।

6. ***राष्ट्रीय नगरीकरण की नीति का अभाव (Lack of National Urbanization Policy)*** – सरकार द्वारा राष्ट्रीय नगरीकरण की नीति का अभाव भी विभिन्न नगरीय समस्याओं के लिए उत्तरदायी है।

7. ***नगरीय निकायों की परंपरागत संरचना (Traditional Structure of Urban Bodies)*** – नगर निकायों की संरचना का विकास दशकों पूर्व हुआ है। वर्तमान समय में नगरों में हुए परिवर्तन के साथ इनका समुचित समायोजन (Adjustment) संभव नहीं हो पाता है। नगरीय समस्याओं के लिए उत्तरदायी कारणों में यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है।

8. ***राजनीतिक व प्रशासनिक इच्छाशक्ति का अभाव (Political and Administrative will Power)*** – नगरीय नियोजन (Urban Planning) हेतु विभिन्न नियमों व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद यह संभव नहीं हो पा रहा है। इसके लिए राजनीतिक व प्रशासनिक इच्छाशक्ति का अभाव प्रमुख कारण है।

9. ***केन्द्र की सीमित भूमिका (Limited Role of the Center)*** – नगर नियोजन राज्य सूची का विषय है जिसके कारण इसमें केन्द्र की भूमिका सीमित हो जाती है। परिणामत: एक समान नगर नियोजन की नीति का निर्माण व पर्याप्त वित्त का अभाव नगरीय समस्याओं को बढ़ा देते हैं।

10. ***राज्यों के पास वित्त का अभाव (States Lack Finance)*** – राज्यों के पास पर्याप्त वित्त का अभाव नगरीय समस्याओं के समाधान न हो पाने हेतु प्रमुख कारण के रूप में विद्यमान हैं।

11. ***विकास कार्यक्रमों का राजनीतिकरण (Politicization of Development Programmes)*** – नगरीय समस्याओं के समाधान हेतु निर्मित विकास कार्यक्रमों का राजनीतिक लाभों हेतु प्रयोग एक सामान्य घटक है। परिणामत: इन कार्यक्रमों का समुचित प्रभाव परिलक्षित नहीं हो पाता है।

12. ***भ्रष्टाचार (Corruption)*** – भ्रष्टाचार ने विकास कार्यक्रमों के समुचित क्रियान्वयन (Implementation) को सर्वाधिक दुष्प्रभावित किया है। परिणामत: नगरीय समस्याएँ अधिक जटिल हो गयी है।

नगरीय समस्याओं के समाधान के प्रयास
(Efforts to Solve Urban Problems)

नगरीकरण तथा औद्योगीकरण आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं अत: राष्ट्र के योजनाबद्ध विकास (Planned Development) के प्रयत्नों में नगरीकरण की दर में तीव्र वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याओं को काबू में लाने की नीतियाँ अपनाई जाती रही है। इन प्रयासों में ज्यादातर गरीब तथा निम्न आय वर्ग के लोगों की स्थिति को सुधारने पर बल दिया जाता रहा है। साथ ही यहाँ आवास एवं जल आपूर्ति की समस्याओं के साथ-साथ नगर विकास की अन्य समस्याओं को हल करने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं।

नगरीय समस्याओं के समाधान की दिशा में किए गए प्रयासों को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है:-

1. सरकार द्वारा स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र एवं विभिन्न NGO के माध्यम से पारिवारिक विघटन (Family Dissolution) रोकने हेतु नि:शुल्क सुझाव एवं सहायता।
2. मद्यपान एवं मादक द्रव्य व्यसन को रोकने हेतु विभिन्न NGO द्वारा नि:शुल्क नशा मुक्ति केन्द्र की स्थापना।
3. नगर विकास हेतु योजना तैयार करने के लिए नगर नियोजन संगठन की स्थापना।
4. प्रमुख नगरीय क्षेत्रों में नगर विकास हेतु नगर विकास प्राधिकरण का गठन।
5. शहरी भूमि अधिकतम सीमा निर्धारण एवं नियमन अधिनियम 1976 के द्वारा भूमि के वितरण को संतुलित करने का प्रयास।
6. 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरीय विकास एवं मलिन बस्तियों में जीवन स्तर में सुधार का प्रयास।
7. दिल्ली हेतु राष्ट्रीय राजधानी नियंत्रण मण्डल की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश हेतु योजनाएं तैयार करना है।

8. नगरीय क्षेत्रों के विकास में नगरवासियों की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए 74वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा नगरीय स्थानीय संस्थाओं का गठन किया गया।
9. केन्द्र सरकार द्वारा इस दिशा में कई कार्यक्रम चलाये गये और इनके माध्यम से नगरीय विकास (Urban Development) का प्रयास किया जा रहा है।
10. राज्य सरकार द्वारा भी विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से नगरीय विकास का प्रयास किया जा रहा है।
11. विभिन्न सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी संगठनों के माध्यम से जैसे आवास एवं नगरीय विकास निगम (HUDCO), पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल विकास बोर्ड, NH DF आदि के द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्रों में अनेक प्रयास किये गये।
12. स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा भी इस दिशा में कई प्रयास किये गये हैं जैसे नगरों में अनाथालयों की स्थापना, मलिन बस्तियों में शिक्षा प्रदान करना, नगरों में वृद्धा आश्रम की व्यवस्था आदि।
13. अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती केन्द्र, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त नगरीय विकास परियोजना आदि के माध्यम से भी इस दिशा में कई प्रयास किये गये।
14. ग्रामीण विकास के द्वारा भी ग्रामीण नगरीय प्रवास पर नियंत्रण हेतु प्रयास किया गया ताकि नगरीकरण को रोका जा सके।
15. अन्य प्रयास–
    - (i) मलिन बस्ती (Dirty Slum) एवं आवास की समस्या हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गयी।
    - (ii) परिवहन व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति लागू की गयी।
    - (iii) पर्यावरणीय समस्या के समाधान हेतु पर्यावरणीय अध्ययन केन्द्र की स्थापना की गयी।
    - (iv) नगरीय विकास के प्रशिक्षण हेतु कोलम्बो प्लान के माध्यम से प्रयास किया गया।
    - (v) मुख्यत: दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण और इस तरह की अन्य समस्याओं के समाधान हेतु जनहित याचिका के माध्यम से समाधान का प्रयास किया गया।
    - (vi) भारत में शहरों की स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु 2008 में शहरी स्वच्छता नीति को लागू किया गया।
    - (vii) शहरी फेरी वालों की समस्या के निराकरण हेतु शहरी फेरी वालों पर राष्ट्रीय नीति लागू किया गया एवं पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण एवं पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2014 को संसद द्वारा अभी हाल ही में पारित किया गया है।

मूल्यांकन एवं सुझाव (Evaluation and Suggestions)

भारत में नगरीकरण जनित समस्याओं और इन समस्याओं के समाधान की दिशा में किये गए प्रयासों के उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में 'नगरीय संस्कृति जनित' (Urban Culture Generated) और 'अति नगरीकरण' (Over urbanization) से जुड़ी कई तरह की नगरीय समस्यायें विद्यमान हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए कई स्तरों पर प्रयास भी जारी हैं।

निश्चित रूप से इन प्रयासों से नगरीय समस्याओं के समाधान की दिशा में कई उपलब्धियां दर्ज की गयी है जैसे आज दिल्ली जैसे नगरों में नगरीय उद्योगों का नगर से बाहर स्थानांतरण, CNG की अनिवार्यता, प्लास्टिक थैले पर रोक जैसे प्रयासों से उल्लेखनीय सफलता हासिल की गयी है। पर्यावरण के क्षेत्र में यह सफलता बम्बई, बंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहरों में भी दृष्टिगत होती है। नगरवासियों को आज शुद्ध पेय जल काफी हद तक उपलब्ध हुआ है और निरंतर प्रयास के द्वारा गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर (Quality of Life) में काफी हद तक सुधार हुआ है। राजीव आवास योजना जैसे कई कार्यक्रमों के द्वारा गन्दी बस्तियों के लोगों के लिए आवास, पेयजल एवं जल निकास की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। आज भारत के नगरों में फ्लाई ओवर एवं मेट्रो रेल आदि के प्रयोग ने काफी हद तक यातायात संबंधी समस्याओं का समाधान (Solution) किया है। निरंतर नई एवं चौड़ी सड़कों का निर्माण, नगर पर भार को कम करने के लिए नगर के बाहर बस्तियों का विकास, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना एवं मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण नगरीय प्रवास को रोकने के प्रयास का काफी हद तक सकारात्मक परिणाम सामने आया है और नगरीय समस्याओं में कमी आयी है। वृद्धों, अनाथ बच्चों एवं महिलाओं के लिए चलाये जा रहे अनाथालय केन्द्रों आदि ने भी संबंधित समस्याओं का काफी हद तक समाधान किया है।

परन्तु उपरोक्त उपलब्धियाँ अभी भी पर्याप्त नहीं हैं और आज भी हम नगरीय समस्याओं के समाधान की दिशा में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। दिल्ली की यमुना नदी, कानपुर की गंगा एवं दक्षिण भारत की महानदी, कावेरी आदि आज भी दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में गिनी जाती है। दिल्ली, मुम्बई और अन्य कई महानगरों में स्वच्छ पीने योग्य जल उपलब्ध नहीं है और लोगों को पानी खरीदकर अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती है। नगरों में परिवहन की समस्या का समुचित समाधान नहीं हो पाया है और ट्रैफिक जाम प्रमुख समस्या बनी हुई है। दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई व बेंगलुरु जैसे महानगरों में 9-11 तथा 5-7 का समय टी.वी. व रेडियो के लिए महत्वपूर्ण होता है जो नगरों में ट्रैफिक जाम के बारे में सूचना देते नजर आते हैं।

मलिन बस्तियाँ आज भी नगरीय समस्या (Urban Problem) बनी हुई है और तमाम प्रयासों के बावजूद रेलवे लाइन के किनारे या नगरों के बीच में ढाबे के रूप में इस तरह की बस्तियां देखी जा सकती हैं। जहाँ लोग आज भी अपेक्षित जन सुविधाओं से वंचित हैं। आज भी आवास के अभाव में नगरीय आबादी का एक बहुत बड़ा भाग सड़कों, प्लेटफॉर्म या फ्लाई ओवर के नीचे जीवन बिताने के लिए विवश है।

व्यक्तिवादिता (Individualism), प्रतिस्पर्धा, मानसिक तनाव एवं आत्महत्या जैसी बढ़ती समस्याएं भारतीय नगरों के नकारात्मक प्रभावों को परिलक्षित (Reflected) कर रहे हैं। नगरों में हो रहे नैतिक पतन एवं कुंठा ने महिलाओं के विरुद्ध छेड़छाड़ बलात्कार व हिंसा जैसी घटनाओं को तीव्र कर दिया है।

इस तरह स्पष्ट है कि भारत में नगरीय विकास की दिशा में हम अभी अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये हैं और इसके लिए जहाँ एक तरफ कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन से संबंधित कमियाँ तो दूसरी तरफ कई तरह के संरचनात्मक कारक (Structural Factors) भी उत्तरदायी रहे हैं।

अत: निष्कर्ष है कि जब तक उपरोक्त कमियों को दूर नहीं किया जाता तब तक नगरीय समस्याओं का समाधान करके आदर्श नगरीय समाज की स्थापना संभव नहीं है। इसके लिए कुछ सुझावों पर अमल किया जा सकता है। सर्वप्रथम नगरों के समानांतर ग्रामीण विकास को संभव बनाना, ग्रामीण नगरीय प्रवास को रोका जाय क्योंकि यह भारत में आज अति नगरीकरण का सबसे प्रमुख कारण है।

✪✪✪✪✪